ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सुविधा

@2233. श्री सुनील कुमार पट्टनायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध नहीं है जब कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यह सुविधा सभी बस्तियों में उपलब्ध कराई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि उपर्युक्त भाग(क) में उल्लेख किया गया है ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इन पर जिलावार केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) और (ख) जी, नहीं । उड़ीसा राज्य समेत देश में शुरू की गयी समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना की सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध है । 1975 में शुरू किये गये इस कार्यक्रम का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जा रहा है । उड़ीसा में 1975-76 में एक आई०सी०डी०एस० परियोजना चलाई गयी थी और राज्य के लिये अब तक स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं की संख्या 105 हो गयी है जो मौजूदा 314 ब्लाकों में से 103 ऐसे ब्लाकों में चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । इसके अलावा दो शहरों के लिये शहरी आई०सी०डी०एस० परियोजनायें उपलब्ध हैं । इनमें से 20 ग्रामीण परियोजनाओं सहित 21 परियोजनायें 1988-89 में स्वीकृत की गयी थीं और यह इस समय चलाई जा रही हैं ।

70 ग्रामीण आदिवासी आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं से प्राप्त फरवरी, 1989 की रिपोर्टों के अनुसार इन परियोजनाओं में 6325 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 6136 केन्द्र 7.14 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान कर रहे थे और 6188 केन्द्र 1.72 लाख बच्चों (3-6 वर्ष के) को पूर्व-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे ।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है ।

इस योजना के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान एकमुश्त दिया जाता है, इस तरह के अनुदान जिलावार नहीं दिये जाते ।

D.T.C. Bus Service on Route Nos. 168 and 913

2234. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the frequencies of bus services of routes 168 and 913 of Delhi Transport Corporation which pass through Ashok Vihar; Laurance Road etc. in North Delhi;

(b) whether it is a fact that quite often the frequency of these services is very long and the number of buses put on these routes is very limited;

(c) whether complaints have been received from time to time about long intervals, frequent break-downs and non-punctuality of these services; and

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1746, 10 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

(d) if so, whether the matter has been gone into, if so, what steps are proposed to be taken to increase the frequency of these services and improve their running conditions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) The frequency of route Nos. 168 and 913 is 40|80 minutes and 23|46 minutes during peak and non-peak hours respectively.

(b) to (d) Number of buses plying on these routes are nine. The services are maintained as per the laid down frequency. Certain complaints regarding irregularity of operation of buses on route No. 168 were received. These were looked into, and instructions were issued for ensuring regular operation of services. There is no proposal to increase frequency on these routes as the services are adequately catering to the needs of the commuters.

Delayed departure|arrival of Kerala Express

2235. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) on how many occasions the Kerala Express was delayed for departure and arrival in New Delhi during January and February, 1989;

(b) what were the causes of these delays; and

(c) what steps Government have taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Departure... 21 days. Arrival...44 days.

(b) Electrification works, alarm chain pulling and equipment failures.

(c) The punctuality will improve soon as electrification works on North|South route get completed.

"क्रेच-सेन्टर" संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुदान

2236. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88 और 1988-89 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दो या अधिक "क्रेच सेंटरों" के संचालनार्थ कितनी संस्थाओं को अनुदानों का अनुमोदन किया गया है और कितनी संस्थाओं के अनुदानों का भुगतान उनके अनुमोदन के पश्चात लंबित पड़ा हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्डों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Conversion of Rail Lines in Punjab

2237. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the details of ongoing railway projects for conversion of metre gauge rail lines into broad gauge in Punjab;

(b) whether more rail lines are proposed to be undertaken for conversion in the near future in that State; if so, what are the details thereof;

(c) whether survey for conversion of Fazilka-Kotkapure rail line was done; if so, what are the details thereof and by when it is likely to be converted; and

(d) whether it is a fact that after conversion, this line would be very useful to meet the defence needs in the border belt; if so, whether Government propose to include this line in the projects for gauge conversion; if so, by when and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA : (a) There are no on-going gauge conversion projects in Punjab.